early 90s, is no longer relevant today. As of now, out of 28 States, you won't find a single State, which is lacking in cash balance. Therefore, the various instrumentalities are being taken care of. This is not the only instrumentality, but this is an important instrumentality. That is why we want that a minimum of 80 per cent should go to the States. And, if in future, the situation arises that State wants to revise it, we will have no problem in taking them into confidence.

श्री राम नारायण साहू: सभापति महोदय, जो इनकम टैक्स का रिफंड होता है, वह हमारा ही पैसा होता है। वह पैसा वहां जमा होता है, हमें वह पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब तक उनकी पूजा नहीं की जाती, तो वे उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते हैं।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री राम नारायण साहू: सर, मेरा यही सवाल है कि जो रिफंड है, वह हमारा पैसा है और वही हमें नहीं मिलता है। हमें अपना पैसा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करनी पड़ती है। सर, यह पूरे राष्ट्र का मामला है। इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जाए। मेरा आप से अनुरोध है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें? सभी सांसद हैं और पूरे भारत के लोग हैं ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Member has raised one issue, and I would like to say that the Government has accepted the responsibility of providing interest in respect of the delay in refund. And, the other day in the other House, I gave a substantial quantum of amount for the year in the last three years, we have paid it because the interest accrues from the 1st of April, in respect of the income-tax refund that I am talking of. So far as the savings rate refunds are concerned, there are a so systems which we shall have to look into. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: साहू जी, आप बैठ जाइए। आपका सवाल खत्म हो गया है।

Establishment of advisory body for schools

*345. SHRI KAMAL AKHTAR:[]

SHRI NAND KISHORE YADAV:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Starred Question 50 given in the Rajya Sabha on 7th July, 2009 and state:

(a) whether Government will constitute an advisory Committee like Railway Advisory Committees, Telecom Advisory Committees etc. at district level in each district of the country comprising of the local MP, MLAs, Principals of Central Schools, representatives from Central Board of Secondary Education (CBSE) and Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) for regulation of minority and private educational institutions recognized and affiliated to CBSE and CISCE;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

[]The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kamal Akhtar.

Statement

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Affiliation Bye-laws of Central Board of Secondary Education (CBSE) and Guidelines for Affiliation of Council for Indian School Certificate Examination (CISCE) have adequate provisions to regulate the functioning of the minority and private schools affiliated to them. Hence, separate Advisory Committees at the district level are not found necessary.

श्री कमाल अख्तर: महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा है कि CBSE और CISCE से संबंधित जितने भी private minority के स्कूल्स हैं, उनमें Advisory Committee नहीं बनाई जाएगी क्योंकि इनको नियमित करने हेतु बहुत प्रावधान हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इतने प्रावधान होने के बावजूद स्टूडेंट्स और जो उनके गार्जियन्स हैं, वे इन संस्थाओं से बहुत त्रस्त हैं। दिल्ली के तो कम से कम मैं पचास संस्थाओं को जानता हूं, यहां पर मैडम बैठी हुई हैं, जैसे सैंट कोलम्बस है, जेसिस मैरी है और डीपीएस आदि हैं। आप गार्जियन्स को तो छोड़िए यदि हम तीन-तीन M.P. किसी की सिफारिश में जाएंगे, तो दो-दो घंटे बैठाकर रखते हैं।

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री कमाल अख्तर: सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनको जमीन सरकार देती है और कभी-कभी तो सरकार उनको सरकारी ऐड भी देती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको नियमित करने के लिए Advisory Committee क्यों नहीं बनाई गई है? अगर कमेटी नहीं है, तो इनको नियंत्रित करने के लिए आप कोई प्रावधान ला रहे हैं या नहीं?

श्री कपिल सिब्बल: सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक शिक्षा का सवाल है और इन institutions का सवाल है, हर एक स्टेट में अपना विधेयक बना हुआ है। जिसके अंतर्गत सभी इंस्टीट्यूशन्स की निगरानी होती है। जहां तक एडवाइजरी कमेटीज का सवाल है, हर विधेयक के अनुसार एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है। यह स्टेट का मामला है, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि केंद्र की सरकार स्टेट के मामले में दखलअंदाजी करे। जैसे दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट है, इसके अंतर्गत एडवाइजरी कमेटीज हैं। इसमें पेरेन्ट्स की रिप्रेजेन्टेशन है, टीचर्स की रिप्रेजेन्टेशन, रजिस्टर्ड सोसायटी या चेरिटेबल ट्रस्ट, जो चलाता है, स्कूल बनाता है, उसकी रिप्रेजेन्टशन है। इसमें ऑलरेडी रिप्रेजेन्टेशन है। यह हर स्टेट में विधेयक के अनुसार है।

श्री कमाल अखतर: सभापति जी, अभी पिछले दिनों यहां पर शिक्षा के अधिकार के संबंध में बड़ी बहस चली। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सी.बी.एस.ई. और सी.आई.एस.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट और अल्पसंख्यक स्कूलों में बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए पच्चीस प्रतिशत कोटा सुनिश्चित करने की कोई योजना है या नहीं है, जिससे शिक्षा के अधिकार का सही मायनों में उपयोग हो सके?

श्री कपिल सिब्बल: सभापति जी, जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, जो विधेयक हमने राज्य सभा में पारित किया है, वह अब लोक सभा में पारित होने के लिए जाएगा। नेबरहुड से दो कैटेगरीज के लोग हैं, इकॉनॉमिकली वीकर सैक्शन और डिसएडवांटेज वीकर सैक्शन, इसके अंतर्गत कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, उसको उनका पच्चीस प्रतिशत रिजर्वेशन करना पड़ेगा।

श्री नन्द किशोर यादव: सभापति जी, जो प्राइवेट और अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, जिन्हें सी.बी.एस.ई और सी.आई.एस.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये मनमाने ढंग से फीस वृद्धि करने का काम करती हैं। ये साल में डेवलपमेंट

चार्ज के रूप में कम से कम पचास या साठ हजार रुपए वसूल करने का काम करती हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई योजना है, जिसके तहत मनमानी फीस वृद्धि और डेवलपमेंट चार्ज की वसूली को नियंत्रित किया जा सके, जिससे मध्यमवर्गीय और गरीब बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ सकें?

श्री सभापति: देखिए, जो सवाल हैं, आप उस पर सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। आपका यह सवाल इससे संबंधित नहीं है।

श्री नन्द किशोर यादव: सभापति जी, इसी से संबंधित है।

श्री सभापति: नहीं, इससे संबंधित नहीं है।

श्री कमाल अख्तर: यह उसी से संबंधित है। उसी के लिए तो एडवाइजरी कमेटी की मांग की है। इसमें कंट्रोल के लिए सारी चीजें आ रही हैं।

श्री सभापति: श्री विजय राघवन।

श्री कमाल अख्तर: सभापति जी, मंत्री जी ने जवाब तो दिया ही नहीं है।

श्री सभापति: इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आपने सवाल नहीं पूछा है, आपने सवाल पर सवाल पूछा है।

श्री कमाल अख्तर: सभापति जी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपकी बारी खत्म हो गई है, ...(**व्यवधान**)...

श्री नन्द किशोर यादव: सभापति जी, यह उसी से संबंधित है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह उससे संबंधित नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री कमाल अख्तर: हमने एडवाइजरी कमेटी किसलिए मांगी है ...(**व्यवधान**)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, it is a matter of concern that these institutions are charging a very exorbitant amount, and it is increasing every year. Unfortunately, this is a matter related to both the State Governments and the Central Government. As far as these types of schools are concerned, the State Governments are not controlling them. The Central Government is virtually giving them permission and they are starting these schools. The State Governments have no control over them; they do not have any right in this regard. So, naturally, we need some social control on these schools. How can we ensure it? The Central Government is giving them permission. They are doing whatever they like in the States, and the State Governments cannot intervene in this matter. So, there is a need for social control over them. Let the Government come up with a proposal how to ensure social control over them.

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, I just want to inform the hon. Member that there are two aspects to this. One, under the various State Acts, recognition is given by the State Governments not by the Central Government. ...*(Interruptions)*... Recognition to the schools is given by the State Governments. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Just a minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: No, no; only an NOG. ...*(Interruptions)*... No recognition. ...*(Interruptions)*....

SHRI KAPIL SIBAL: Allow me to answer. ...*(Interruptions)*... As far as affiliation is concerned, that is given by the Board. There is a difference between recognition and affiliation. ...*(Interruptions)*... You asked the question, I am trying to answer it, through the Chairman. So, the point I am trying to make is, once recognition is given by the State Government and affiliation is given by us, under the various State statutes.. ....*(Interruptions)*...

श्री ब्रजेश पाठक: स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल को मान्यता नहीं देती ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठिए ...(**व्यवधान**)...

SHRI KAPIL SIBAL: Under the various State statutes fees are controlled by the State Acts. For example, various State Acts say that the fees charged should be commensurate with the services rendered. ...*(Interruptions)*...

श्री ब्रजेश पाठक: आप गुमराह कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सवाल का जवाब तो सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)... आप सुन तो लीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री कमाल अख्तर: सभापति जी, हम सही जवाब के लिए यहां बैठे हैं, ...(**व्यवधान**)... आप शेल्टर दे रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप जवाब नहीं सुनेंगे तो क्या फायदा है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: इससे कोई फायदा नहीं है ...(**व्यवधान**)...

SHRI KAPIL SIBAL: So what I was trying to say was that under the various State Acts, capitation tee and donations are prohibited. I have the Delhi School Education Act with me. I can point out provisions in terms of both capitation fee and donations under the Delhi School Education Act are prohibited. If there are schools, which are charging that, they can be taken to court. May I also point out two other things? There are Constitutional provisions both with respect to minority schools and private unaided schools. There are several judgements of the Supreme Court, which relate to the fact that the State Governments and the Central Government would find it difficult in the light of those provisions to interfere with these processes in various schools of this category in various States. ...*(Interruption)*...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, separate Advisory Committees at the district levels are not found necessary because the affiliation with the Central Board of Secondary Education is sufficient. But in the Right to Education Bill, there is a provision for School Level Development Committee. Therefore, I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, whether the Government has any plan to change the existing CBSE bylaws and provisions for granting affiliation, etc., etc. in accordance with the Right to Education Bill.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, there are two separate issues here. As far as schools set up under the Right to Education Act are concerned, these are the Government schools and will be governed by the provisions of that Act. But the question relates here to private unaided schools and minority

schools. As he knows, we cannot interfere in the management of the private unaided schools and minority schools. That is the law of this country. So, we will not be able to bring the CBSE guidelines in consonance with what is being suggested.

DR. K. MALAISAMY: Sir, from the reply of the hon. Minister, according to him, the affiliation bylaws and guidelines are 'adequate'. He has used the word 'adequate'. Provisions to regulate the functioning of minority and private schools are adequate. It is his reply, Sir. According to me, when the existing procedure and provisions are adequate to take care of the problem, why are there are umpteen no. of complaints in terms of looting by the private schools when people come for admission? They are charging like anything and they are going too far. It is in everybody's knowledge that the private institutions and the minority institutions are exploiting the public. I would like to know whether this kind of complaints are coming to the notice of the Government. If so, whether your existing procedure or existing law or existing system or whatever you call it, is adequate. According to me, it is totally inadequate and totally uneffective.

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, the comment which is being made is not being made on any Central law but on the State laws because all this is done under the State Acts. ...*(Interruptions)*... I would request the hon. Member to go to the Chief Minister of the State that he represents and tell him how inadequate his laws are. If they wish to take action, we will support them.

Joint working group for education

*346. SHRI RAJEEV SHUKLA:
DR. T. SUBBARAMI REDDY:[]

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a first of its type a joint working group on education has been set up between the United States of America (USA) and India;

(b) if so, whether this joint working group will have academic and Government representatives from both countries;

(c) if so, to what extent the USA has agreed to provide assistance and funds to India for improving higher education; and

(d) whether India has allowed foreign institutions to come in the country and the countries which have agreed to provide financial assistance for higher education?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) During the visit of Under Secretary, Political Affairs, US State Department in the month of June 2009, a Joint Working Group (JWG) headed by the Union Minister of Human Resource Development and his counterpart US Secretary of Education, has been proposed for cooperation in

[]The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy.